प्रेस विज्ञप्ति

28 मार्च, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, इंचार्ज कम्युनिकेशंस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने आज निम्नलिखित बयान जारी कियाः–

"पठानकोट उग्रवादी हमले की तथाकथित जांच के लिए भारत आई 'पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम' को बिना रोकटोक के सामरिक महत्व के संस्थानों में प्रवेश दिया जाना और एक तरह से उनके स्वागत में भारत सरकार द्वारा रेड कार्पेट बिछाना, वो भी तब, जब पाकिस्तान द्वारा आज तक भारत सरकार को 'लेटर रोगेटरी' न जारी किया गया हो, यह अपने आप में पूरी प्रक्रिया के औचित्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते के बारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है।

मोदी सरकार ने पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे गंभीर यूटर्न लिया है, जिनके द्वारा आए दिन भारत में उग्रवाद निर्यात किया जाता है, व इसके चलते हमारे नागरिकों और सेना के जवानों को सर्वोच्च कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तान ज्वाईंट इन्वेस्टिगेशन टीम का आना यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी, जिसमें हम स्टेट और नॉनस्टेट एक्टर्स में कभी फर्क नहीं करते, को अब बदल रही है और मोदी सरकार पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स को उग्रवाद फैलाने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स से अलग मानती है। इन गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पूरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ चकित हैं और देश के लोग चिंता में हैं। कई महत्वपूर्ण प्रश्न, मुद्दे और विषय हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गंभीर चिंतन कर देश को जबाव देना चाहिए। देश की ओर से हम इनकी व्याख्या कर मोदी जी से जबाव मांगना चाहेंगे :–

सबसे पहले, क्या प्रथम दृष्टि से अगर देखें, तो जो खुद दोषी हैं, वो क्या खुद की ही तफ्तीश करने हमारे देश में आए हैं?

दूसरा, बीजेपी सरकार द्वारा पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन टीम को, पहले हमारे देश में बुलाना, सामरिक महत्व के अलग अलग संस्थानों में जाने की इजाजत देना, समेत पठानकोट एयरबेस के, क्या यह दर्शाता है कि मोदी सरकार का यह मानना है कि पठानकोट उग्रवादी हमले में पाकिस्तान सरकार के किसी व्यक्ति या संस्था का कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका नहीं थी और यह सब केवल नॉनस्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया था, यानि उन उग्रवादी संस्थाओं के द्वारा, जो पाकिस्तान की सरजमीं का इस्तेमाल हिंदुस्तान में उग्रवाद फैलाने के लिए करते हैं, बगैर पाकिस्तान या आईएसआई की भूमिका के?

तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की वर्षों से, दशकों से डिक्लेयर्ड नीति रही है कि पाकिस्तान में स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई अंतर नहीं, खासतौर से जब हिंदुस्तान में उग्रवाद के निर्यात का प्रश्न आता है। वो लश्कर–ए–तैयबा हो, वो जैश–ए–मोहम्मद हो, वो अलकायदा हो या वो किसी और नाम से जानी जाने वाली उग्रवादी संस्थाएं हों। हमने बार बार आपस में बातचीत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत में सभी फोरम्स पर यह कहा है कि पाकिस्तान की एजेंसीज़, खासकर आईएसआई का हाथ, इन

सभी उग्रवादी संगठनों की मदद में रहता है और पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई अंतर नहीं। तो क्या भारत सरकार ने उग्रवाद के बारे और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे एक महत्वपूर्ण यू–टर्न ले लिया है? क्या उनका अब ये मानना है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आदि का हमारे देश भारत में उग्रवाद फैलाने में कोई हाथ नहीं? अगर भारत में पाकिस्तान से आने वाला उग्रवाद केवल नॉनस्टेट एक्टर्स जैसे जैश–ए–मोहम्मद या लश्कर–ए–तैयबा के द्वारा किया जा रहा है और उनको कोई मदद पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई के द्वारा नहीं दी जा रही? यह गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, जिसका जबाव मोदी जी को देना चाहिए।

चौथा, इस बात की क्या गारंटी मोदी सरकार को है कि पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो हमारे देश में आई है, वो तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करने के बाद उन्हीं नॉनस्टेट एक्टर्स यानि उन्हीं सारे उग्रवादी संगठनों के हक में तफ्तीश का निर्णय नहीं कर देगी?

पांचवां, पाकिस्तान ने आज तक हमारे देश को पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा सबूत इकट्ठे करने बारे कोई लेटर रोगेटरी जारी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इकट्ठे किए गए सबूत पाकिस्तान में किसी भी अदालत में जैश–ए–मोहम्मद या अन्य उग्रवादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर कोई सबूत इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता और अगर उनसे उग्रवादियों को सजा ही नहीं मिल सकती, तो फिर पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम का हिंदुस्तान में आने और इस सारी तफ्तीश के ढ़कोसले के क्या मायने बचे हैं? अगर उस सबूत को आपको इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम के हमारे देश में आने और तफ्तीश करने के पीछे सही मंशा क्या है? इसका जबाव भारत सरकार को देश के लोगों को देना चाहिए।

छठा, आईएसआई, जिसके बारे में यह मशहूर है कि हमारे देश के खिलाफ जो उग्रवादी संगठन काम करते हैं, उनको संरक्षण और प्रोत्साहन देती है, उसके एक अधिकारी का इस पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनकर आने के पीछे क्या औचित्य है? मोदी सरकार इसकी इजाजत क्यों दे रही है?

सातवां और महत्वपूर्ण सवाल है कि कुख्यात उग्रवादी संस्था, जो जैश–ए–मोहम्मद है, उसका पूरे पठानकोट उग्रवादी हमले में भूमिका सबूतों के आधार पर स्पष्ट है। ऐसे में मौलाना मसूद अजहर, जो कुख्यात उग्रवादी हैं और जैश–ए–मोहम्मद का प्रमुख है, व उसका भाई अब्दुल राउफ, जो पठानकोट उग्रवादी हमले के उग्रवादियों के हैंडलर है और उसी संगठन के एक और उग्रवादी काशिफ जान, जो पठानकोट उग्रवादी हमले का दूसरा हैंडलर है, उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार के द्वारा कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या पाकिस्तान सरकार, क्या श्री नवाज शरीफ, जो मोदी जी के नए मित्र हैं; क्या पाकिस्तान की आईएसआई क्या पाकिस्तान की आर्मी ने भारत सरकार को कोई आश्वासन दिया है कि वो फौरी तौर से जैश–ए–मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल राउफ, काशिफ जान जैसे उग्रवादियों को गिरफ्तार करेंगे, संस्थाओं को बैन करेंगे और इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? अगर ऐसा है, तो मोदी जी देश को इस बारे में बताएं।

आठवां, आज तक भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बारे क्या मदद मांगी है? दीनानगर, गुरदासपुर में जो उग्रवादी हमला हुआ, उसके उग्रवादियों और हत्यारों और उसके षडयंत्रकारियों को किस प्रकार पाकिस्तान सजा देगा? क्या उन उग्रवादियों और उनके मित्रों को पाकिस्तान हमारे देश को हैंडओवर करेगा, ताकि हम उनके खिलाफ मुकदमा चला सकें या पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा? ऐसे ही एक उग्रवादी हमला, जो ऊधमपुर, जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसके उग्रवादियों को पाकिस्तान किस प्रकार सजा देगा?

क्या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की इस बारे वार्ता हुई है या ये सारी कार्यवाही एक डेड–एण्ड और ढकोसला हैं? 26/11 के मुंबई उग्रवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पुख्ता सबूत, जिनसे उग्रवादियों को सजा हो सकती थी, डॉज़ियर के रूप में अनेकों बार पाकिस्तान की सरकार को दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की उस समय की यूपीए सरकार ने सारे सबूत रखे थे। इसके बावजूद भी आज तक जकीउर्रहमान लखवी और उसकी उग्रवादी संस्था, लश्कर–ए–तैयबा, खुलेआम पाकिस्तान में सरकार के संरक्षण में अपनी उग्रवादी गतिविधियां चलाते हैं और पाकिस्तान की सरजमीं का भारत के खिलाफ प्रपोगंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या मौजूदा इन्वेस्टिगेशन भी एक डेड एण्ड में बदल जाएगी?

ये सारे प्रश्न हैं, जिनका जबाव कांग्रेस पार्टी देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांगती है?